हम राजस्थानी • जलवायु परिवर्तन बड़ा खतरा

प्रदेश के सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी 'जलवायु योजना'

नीति-निर्णय

प्रदीप मेहता
सेक्रेटरी जनरल कट्स इंटरनेशनल
psm@cuts.org

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हाल ही में गांधीनगर में आयोजित 'चौथी वैश्विक रिन्यूएबल एनर्जी निवेश बैठक में कहा था, 'विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हमने ऊर्जा के क्षेत्र में कार्ययोजना तैयार कर ली है।' जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि पहले से शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र वाला राजस्थान जलवायु परिवर्तन से और अधिक प्रभावित हो रहा है। इससे जुड़े परिणामों को हम इस मानसून अत्यधिक बारिश और अस्त-व्यस्त जीवन के रूप में देख चुके हैं।

प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है जिसका मुख्य स्रोत जल है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था और किसानों की आय इससे गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। औसत तापमान में वृद्धि राज्य में जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रही है। हीटवेव और सूखा जैसी घटनाएं लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका के साथ वन्यजीव संपदा और जैव-विविधता पर भी सीधा प्रभाव डाल रही हैं। इसलिए, राजस्थान में एक प्रभावी जलवायु कार्य योजना की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और राज्य को एक स्थायी भविष्य की ओर ले जाना है। यह योजना न केवल पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जरूरी है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है।

इसके लिए राज्य सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे । इसमें पहला है रिन्यूएबल एनर्जी का प्रसार। हम रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत में दूसरे स्थान पर हैं। लेकिन अभी भी 78% ऊर्जा के लिए पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता के कारण सौर व पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जल संरक्षण के प्रयासों को भी तेज करने की आवश्यकता है। इसके लिए पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों का पुनरुद्धार और प्रोत्साहन किया जाना चाहिए।

जलवायु-संवेदनशील सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम के उपयोग और रेनवॉटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए। साथ ही जलवायु-संवेदनशील कृषि पद्धतियों का विकास भी एक अहम कदम हो सकता है। सूखा- प्रतिरोधी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगा। किसानों को सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में भी जागरूक करना श्रेयस्कर होगा। इसके लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को साथ आना होगा।

राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण से जलवायु पर असर पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी पहल के तहत, सरकार को पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ इमारतों और हरित बुनियादी

> **राजस्थान में एक प्रभावी जलवायु कार्य योजना की जरूरत है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर और राज्य को एक स्थायी भविष्य की ओर ले जाए । यह पर्यावरण के साथ प्रदेश वासियों के लिए भी श्रेयस्कर साबित होगी।**

ढांचे को बढ़ावा देना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन, साइकिल शेयरिंग प्रणाली को बढ़ावा देना और निजी वाहनों की संख्या को नियंत्रित करना भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रभावी उपाय हैं।

राजस्थान पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। सरकार को ऐसे पर्यावरण-संवेदनशील पर्यटन स्थलों का विकास करना चाहिए, जो स्थानीय पर्यावरण और संस्कृति को संरक्षित करें। इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना राज्य के पर्यावरणीय और आर्थिक विकास के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है।

राज्य सरकार को जलवायु कार्य योजनाओं के वित्तपोषण के लिए नए स्रोतों की तलाश करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र से वित्तीय सहयोग प्राप्त करने के लिए साझेदारियों का निर्माण करना आवश्यक है। इसके साथ ही, जलवायु परिवर्तन से जुड़े अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना चाहिए। इस तरह ठोस जलवायु कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करके राजस्थान एक स्थायी और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)